नगदीहीन समाज के 4 खतरे

नगद मुद्रा बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाएगी। हाल में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि यूके में 2014 में पहली बार ऐसा हुआ है कि नगदहीन खरीदारी ने नगदी खरीदारी को पीछे छोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इस बदलाव को नई तकनीकों ने खूब बढ़ावा दिया है - मोबाइल ऐप्स, इलेक्ट्रॉनिक काड्र्स वगैरह।

यह सुविधाजनक तो है, लेकिन क्या बिना नगद का समाज खतरनाक भी हो सकता है? बैंक लोगों के हित के अच्छे रक्षक साबित नहीं हुए हैं और टेक्नॉलॉजी कंपनियां हमारी गोपनीयता के प्रति लापरवाह रही हैं। अतः यह सवाल उठना लाज़मी है। युनिवर्सिटी ऑफ कुम्ब्रिया के जैम बेन्डेल द्वारा हाल ही में बड़े स्तर पर *मनी एंड सोसायटी* ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है इसमें 4 खतरों से आगाह किया गया है।

पहला मुद्दा है उपभोक्ता संरक्षण का। ई-पेमेंट सिस्टम हमारी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी है। क्या होगा यदि किसी को इस पेमेंट सिस्टम से काट दिया जाए? इसके चलते जवाबदेही व नियमन की नई व्यवस्था ज़रूरी हो जाती है।

कुछ प्रतिस्पर्धा सम्बंधी मुद्दे भी हैं। पूरे विश्व के क्रेडिट कार्ड बाज़ार का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वीज़ा और मास्टरकार्ड खाता धारकों का है। यानी इन कंपनियों के पास भुगतान के संचालन का एकाधिकार है। इस एकाधिकारपूर्ण बाज़ार में विविधता लाने के लिए अनुकूल नीतियों को अपनाया जाना चाहिए।

ई-पेमेंट व्यवस्था में भरपूर डैटा होता है, इसलिए गोपनीयता एक अलग चिंता का विषय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जानबूझकर ही छोड़ा जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर निगरानी को लेकर कोई सहमति नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने गोपनीयता को बुनियादी मानव अधिकार मान्य किया है। हमारा सामान्य कम्युनिकेशन डैटा बड़े स्तर पर जासूसी संस्थाओं के हाथ में होता है। ऐसे में अब ई-पेमेंट क्रांति के तहत हमारे वित्तीय आंकड़ों की गोपनीयता पर तलवार लटक रही है।

और नगदीहीन समाज की सबसे बड़ी चिंता है कि भुगतान तंत्र का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में हो सकता है। राजनैतिक सत्ता पेमेंट कंपनियों या बैंकिंग नेटवर्क को ऐसी इकाइयों की पहुंच रोकने को कह सकती है, जो सत्ता के लिए नुकसानदायक हैं। जैसे 2011 में कुछ यूएस राजनेताओं के कहने पर विकीलीक्स के खातों को ब्लॉक किया गया था। इसी तरह 2012 में युरोपीय संघ ने बेल्जियम-आधारित नेटवर्क द्वारा ईरानी बैंकों के साथ सारे लेन-देन को निलंबित कर दिया था और रशियन बैंकों को भी ब्लॉक करने के लिए दबाव बनाया गया था।

हो सकता है नगद आहरण पुराना पड़ गया हो, लेकिन इसे पूरी तरह से हटाने के लिए और अधिक पुख्ता सुरक्षा व नियमन व्यवस्था की ज़रूरत होगी। नहीं तो हमारे भुगतान तंत्र में घात का खतरा बना रहेगा जो कोई नहीं चाहेगा। ***(स्रोत फीचर्स)***